(ग) दिशानिर्देशी में इस बात का प्रावधान है कि राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों में से कम से कम 10% निधियों का उपयोग गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से शौचालयों का निर्माण करने में किया जाए। इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों को शौचालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय महिला कोष तथा कर्पाट द्वारा निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन

3164. **श्री नगेन्द्र नाथ ओझा**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हो कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने जून, 1993 से मई, 1994 तक देश में विभिन्न जिलों की 4700 पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना का समवर्ती मूल्यांकन कराया था और यह पाया गया था कि 49.47 प्रतिशत कार्य निधियों की कमी के कारण से पूरे नहीं किये जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए क्या अवश्यक कदम उठाए गए हैं और उक्त अधूरे कार्य में आने वाली अड़चनों को दूर करने के संबंध में यदि कोई उपलब्धि है तो उसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) जी हां, देश में जून, 1993 से मई, 1994 तक विभिन्न जिलों की 4635 पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के कराए गए समवर्ती मूल्यांकन से पता चला है कि विभिन्न कारणों की वजह से 14.12 प्रतिशत कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका था। ऐसे 49.74 प्रतिशत अपूर्ण कार्यों की वजह निधियों का अभाव था।

(ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना को तैयार करते समय नए कार्यों को शुरू करने की बजाय अपूर्ण कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी-जिला परिषद् द्वारा ऐसा कोई भी कार्य शुरु नहीं किया जा सकता है जिसे दो वित्तीय वर्षों के भीतर पूरा न किया जा सकता हो।

Credit linked self employment package scheme under IRDP

3165. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have initiated credit linked self employment package scheme under Integrated Rural Development Programme;

(b) if so, the details thereof and the number of rural people benefited under the said scheme during 1996-97;

(c) whether there are reports of rampant corruption under the said scheme; and

(d) if so, the corrective measures being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Integrated Rural Development Programme (IRDP) is a credit-linked self employment programme implemented by this Ministry.

(b) Under IRDP, selected families below the Poverty Line are provided productive assets for sustainable income generation by way of term credit by the financial institutions and subsidy by the Government.

(c) and (d) Whenever any complaint regarding implementation of the programme is received in the Ministry, appropriate action is taken.

उत्तर प्रदेश में जल संकट

3166. **श्री रामगोपाल यादव**:
श्री ईस दत्त यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है जिससे पेयजल और सिचांई का घोर संकट उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संकट को दूर करने के लिए कोई व्यापक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (ग) जी, हां, उत्तर प्रदेश सहित देश के इनेक हिस्सों में जल स्तर गिर रहा है। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और कर्नाटक आदि जैसे कुछ हिस्सों में यह गिरावट अधिक